

RNA : Real News Analysis

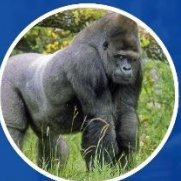
DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

Key Point

DATE
सितम्बर
16
2024

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index



By Ankit Avasthi Sir

भास्कर पहल : भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की है। 'स्टार्टअप इंडिया' कार्यक्रम के तहत, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) नामक एक अभूतपूर्व डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। यह मंच स्टार्टअप, निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

भारत का नवाचार और उद्यमिता नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य भारत को नवाचार और उद्यमिता में एक वैश्विक नेता बनाना है। भास्कर पहल स्टार्टअप आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भास्कर: केन्द्रीकृत मंच से नवाचार को बढ़ावा:

भारत में वर्तमान में 1,46,000 से अधिक DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जो इसे दुनिया के सबसे सक्रिय स्टार्टअप हब में से एक बनाते हैं। भास्कर एक ऐसा केन्द्रीकृत मंच है जो उद्यमियों और निवेशकों की चुनौतियों का समाधान प्रदान करता है। यह विचार से क्रियान्वयन तक उद्यमशीलता की यात्रा को सहज बनाने में मदद करेगा।

प्रमुख विशेषताएं:

भास्कर की विशेषताएं इसे दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाने का प्रयास करती हैं:

- ✓ **नेटवर्किंग और सहयोग:** यह मंच स्टार्टअप, निवेशकों, और अन्य हितधारकों को एक साथ लाकर समेकित बातचीत को बढ़ावा देगा।
- ✓ **संसाधनों की केन्द्रीकृत पहुंच:** स्टार्टअप्स को तत्काल महत्वपूर्ण संसाधनों और ज्ञान तक पहुंच प्रदान कर, उन्हें तेजी से निर्णय लेने और स्केलिंग में मदद करेगा।
- ✓ **व्यक्तिगत पहचान:** प्रत्येक हितधारक को एक अद्वितीय 'भास्कर आईडी' प्रदान की जाएगी, जिससे प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत अनुभव और आसान बातचीत संभव होगी।
- ✓ **सूचना तक पहुंच में वृद्धि:** उपयोगकर्ता प्रासंगिक संसाधनों, सहयोगियों और अवसरों को आसानी से खोजने के लिए शक्तिशाली खोज सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे।

भारत के वैश्विक ब्रांड का समर्थन:

भास्कर भारत की वैश्विक नवाचार प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अधिक सुलभ हो जाएगा।

भास्कर के लाभ: स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना:

भास्कर का शुभारंभ नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को गति देने में सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह स्टार्टअप्स, निवेशकों और अन्य हितधारकों के लिए एक साझा मंच बनेगा, जहां विचारों का आदान-प्रदान और विकास को बढ़ावा मिल सकेगा।

भविष्य की दिशा:

भास्कर प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ, भारत सरकार नवाचार और उद्यमशीलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्लेटफॉर्म भारत को वैश्विक आर्थिक विकास और उद्यमिता में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।



Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
Government of India

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रमुख मंत्रालय है जो देश के व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह मंत्रालय देश के व्यापार नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करता है, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।

मंत्रालय के प्रमुख कार्य:

- ✦ **व्यापार नीति:** मंत्रालय देश के व्यापार नीति का निर्धारण करता है, जिसमें निर्यात और आयात शुल्क, व्यापार समझौते, और विदेशी व्यापार नीतियां शामिल हैं।
- ✦ **उद्योग प्रोत्साहन:** मंत्रालय घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम लागू करता है, जैसे कि 'मेक इन इंडिया' पहल।
- ✦ **विदेशी निवेश:** मंत्रालय विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाता है और विदेशी निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करता है।
- ✦ **बौद्धिक संपदा:** मंत्रालय बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए कार्य करता है।
- ✦ **उपभोक्ता संरक्षण:** मंत्रालय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाता है और उनका कार्यान्वयन करता है।

मंत्रालय के संगठन:

मंत्रालय विभिन्न विभागों और संगठनों में विभाजित है, जिनमें शामिल हैं:

- ✦ विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
- ✦ एंटी डंपिंग महानिदेशालय (DGAD)
- ✦ भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (TPI)

20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद

एमएसडीसी की 20वीं बैठक में समुद्री क्षेत्र की नई चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। संकटग्रस्त जहाजों के लिए शरण स्थल (पीओआर) की स्थापना और बंदरगाहों की सुरक्षा में सुधार के लिए रेडियोधर्मी पहचान उपकरण (आरडीई) का विकास, प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहे। इसके साथ ही, नाविकों को प्रमुख आवश्यक कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार की दिशा में कदम उठाए गए।

एमएसडीसी में शुरु की गई प्रमुख पहलें:

- ✓ **भारतीय समुद्री केंद्र (आईएमसी): एक नीति थिंक टैंक** : इस बैठक में भारतीय समुद्री केंद्र की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र में नवाचार, ज्ञान साझा करने और रणनीतिक योजना को बढ़ावा देना है। यह केंद्र विभिन्न समुद्री हितधारकों को एक साथ लाकर देश के समुद्री विकास को गति देगा।
- ✓ **भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र (आईआईएमडीआरसी) : "भारत में समाधान"** पहल के तहत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह केंद्र समुद्री लेन-देन की बहु-मॉडल, बहु-अनुबंध, और बहु-क्षेत्राधिकार चुनौतियों का समाधान करेगा।
- ✓ **राष्ट्रीय एकल स्विडकी प्रणाली पर राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति (एनएसपीसी) : राष्ट्रीय एकल स्विडकी प्रणाली प्लेटफॉर्म पर एनएसपीसी एप्लीकेशन लॉन्च** किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है।
- ✓ **राज्य-स्तरीय नवीन पहलों का प्रदर्शन:**
 - **केरल की ड्रेजिंग मुद्दीकरण तकनीक** : केरल ने ड्रेजिंग के लिए अपनी मुद्दीकरण तकनीक का प्रदर्शन किया, जो राज्य के राजस्व को बढ़ाने में मदद करेगी।
 - **गुजरात की बंदरगाह-आधारित शहरी विकास परियोजनाएं** : गुजरात ने बंदरगाह-संचालित शहरी विकास परियोजनाओं की सफल केस स्टडी प्रस्तुत की, जो राज्य के शहरी विकास में बंदरगाहों की भूमिका को दर्शाती है।
- ✓ **भारत के सबसे बड़े ड्रेजर का निर्माण** : कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में रॉयल आईएचसी हॉलैंड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा ड्रेजर बनने का काम शुरू हुआ। यह परियोजना देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाएगी।
- ✓ **मेगा शिपबिल्डिंग पार्क योजना** : बैठक में मेगा शिपबिल्डिंग पार्क योजना पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में जहाज निर्माण क्षमताओं को एकीकृत कर दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
- ✓ **राज्य रैंकिंग फ्रेमवर्क: स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टिकाऊ प्रथाएं** - तटीय राज्यों के बीच राज्य रैंकिंग फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन वृद्धि और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा। इससे राज्यों को बेहतर समुद्री विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा।



समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी)

- ✓ **समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी)** एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है जो समुद्री क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ✓ एमएसडीसी की स्थापना मई 1997 में जहाजरानी मंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें समुद्री राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बंदरगाहों के प्रभारी मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- ✓ इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों का समन्वित विकास सुनिश्चित करना है। एमएसडीसी राज्य सरकारों के परामर्श से मौजूदा और नए छोटे बंदरगाहों के भविष्य के विकास का मूल्यांकन करता है, जिसमें सीधे या कैरिव उपयोगकर्ताओं और निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाता है।
- ✓ इसके अतिरिक्त, एमएसडीसी छोटे बंदरगाहों, कैरिव बंदरगाहों और निजी बंदरगाहों के विकास की निगरानी करता है, ताकि प्रमुख बंदरगाहों के साथ उनका समन्वित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- ✓ यह सड़क, रेल, और अंतर्देशीय जलमार्ग (आईडब्ल्यूटी) जैसी अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का भी आकलन करता है और संबंधित मंत्रियों को उचित सिफारिशें प्रदान करता है।

री-इन्वेस्ट 2024

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आयोजित चौथा वैश्विक RE-INVEST नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी 16 से 18 सितंबर 2024 तक महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक मंच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है।

RE-INVEST 2024: वैश्विक ऊर्जा नेताओं का मिलन स्थल-



- ✓ इस आयोजन में सरकार के अधिकारी, उद्योग जगत के नेता, निवेशक, शोधकर्ता और नीतिनिर्माता शामिल होंगे। प्रदर्शनी में नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन में ऊर्जा के भविष्य पर चर्चा होगी, जिसमें वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने वाली तकनीकें, नीतियां और रुझान शामिल होंगे।
- ✓ सहयोग और निवेश के नए अवसर: यह अद्वितीय मंच भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग, ज्ञान-विनिमय और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा। इस आयोजन का उद्घाटन पिछले संस्करणों की तरह इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति से गौरवान्वित होगा।

25,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी:

- ✦ इस साल के आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों, विभिन्न राज्य और देश सत्रों, तकनीकी सत्रों और अत्याधुनिक प्रदर्शनी की योजना है। यह कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को आकार देने वाली नीतियों और नवीनतम तकनीकी नवाचारों की खोज के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य तय किया जा सके।

RE-INVEST के बारे में -

RE-INVEST भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य दुनिया को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता से अवगत कराना और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आयोजित एक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी है, जो वैश्विक निवेशकों, डेवलपर्स, निर्माताओं और इनोवेटर्स को एक मंच पर लाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को तेजी से बढ़ावा देना और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को वैश्विक निवेशकों से जोड़ना है।

RE-INVEST के सफल संस्करण:

पहला RE-INVEST इंडिया 2015 में आयोजित हुआ था, इसके बाद 2018 और 2020 में भी इसके आयोजन किए गए। इन सम्मेलनों ने भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में निवेशकों और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों को आकर्षित किया, जिससे यह आयोजन सफल रहा।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण:

RE-INVEST का एक्सपो, मीट और फोरम भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल भारत के स्वच्छ ऊर्जा बाजार की संभावनाओं को उजागर करता है, बल्कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को भी रेखांकित करता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकास के लिए समर्पित है। यह मंत्रालय देश को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए अनेक पहल करता है।

MNRE का उद्देश्य:

- ✦ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और छोटे जलविद्युत परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना और बढ़ावा देना।
- ✦ ऊर्जा सुरक्षा: देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना।
- ✦ पर्यावरण संरक्षण: पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में योगदान देना।
- ✦ ग्रामीण विकास: ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच बढ़ाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

MNRE के प्रमुख कार्य:

- ✓ नीति निर्माण: नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना।
- ✓ वित्तीय सहायता: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ✓ अनुसंधान और विकास: नई तकनीकों और उत्पादों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- ✓ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करना।

सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी- विनेत्र नौसेना में शामिल

13 सितंबर, 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर द्वारा आईएनएस सातवाहन, विशाखापत्तनम में कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी (विनेत्र) का उद्घाटन किया गया। इस सुविधा का उद्देश्य संकटग्रस्त कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बियों से चालक दल की भागने की क्षमताओं को बढ़ाना है।

- ✓ **स्वदेशी डिजाइन और आत्मनिर्भरता:** यह ट्रेनिंग फैसिलिटी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप है। इसका निर्माण **टर्नकी परियोजना** के रूप में मैसर्स एलएंडटी डिफेंस द्वारा किया गया है। इस परियोजना के तहत एक पांच मीटर का एस्केप टॉवर स्थापित किया गया है।
- ✓ **प्रशिक्षण के उद्देश्य और महत्व :** कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी का उपयोग कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के चालक दल को बेसिक और रिफ्रेशर दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चालक दल संकट की स्थिति में पनडुब्बी से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कौशल में दक्ष हो जाएं।
- ✓ **सुरक्षा और परिचालन तत्परता में योगदान :** इस ट्रेनिंग फैसिलिटी को "विनेत्र" नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है "ट्रेनर"। यह पनडुब्बी के चालक दल के बीच भरोसा बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि वे समुद्र के अंदर पानी के नीचे की किसी भी आपात स्थिति में बच निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह सुविधा भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करती है।

सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी (SETF) के बारे में :

सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी (SETF) एक विशेष प्रशिक्षण केंद्र है जो सबमरीन या पनडुब्बी में आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की ट्रेनिंग प्रदान करता है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य सबमरीन के चालक दल को उन तकनीकों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करना है जो सबमरीन के आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित एस्केप को सुनिश्चित करते हैं।

SETF का महत्व:

- ✦ **सुरक्षा सुनिश्चित करना:** यह प्रशिक्षण सबमरीन के चालक दल को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित ढंग से बाहर निकलने के तरीके सिखाता है, जो जीवन रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
- ✦ **आपातकालीन तैयारी:** यह सुविधा आपको आपातकालीन स्थितियों के लिए पूरी तरह से तैयार करती है, जिससे सबमरीन संचालन के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।
- ✦ **उपकरण और तकनीक का अभ्यास:** प्रशिक्षण के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीकें सबमरीन के संचालन में शामिल सभी लोगों के लिए आवश्यक हैं।



SETF के प्रमुख घटक

- ✓ **प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर:** इन सिमुलेटर्स का उपयोग सबमरीन की आपातकालीन स्थितियों को यथार्थवादी ढंग से अनुभव करने के लिए किया जाता है, जिसमें चालक दल को विभिन्न प्रकार के आपातकालीन परिदृश्यों में प्रशिक्षित किया जाता है।
- ✓ **एस्केप ट्यूब्स और कंटेनर:** इनका उपयोग वास्तविक परिस्थितियों की नकल करने के लिए किया जाता है, जहां प्रशिक्षुओं को सबमरीन से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने का अभ्यास कराया जाता है।
- ✓ **आपातकालीन प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएँ:** प्रशिक्षकों द्वारा सभी आवश्यक एस्केप तकनीकों और प्रोटोकॉल की जानकारी दी जाती है, जिसमें सबमरीन के विभिन्न हिस्सों से बाहर निकलने के सही तरीके शामिल होते हैं।
- ✓ **सुरक्षा उपकरण:** एस्केप ट्रेनिंग को विभिन्न सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो सबमरीन के आपातकालीन एस्केप के लिए आवश्यक होते हैं।
- ✓ **वास्तविक अनुभव:** व्यावहारिक अभ्यास के दौरान, प्रशिक्षुओं को वास्तविक परिस्थितियों की तरह अनुभव कराया जाता है, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में ठंडे दिमाग से निर्णय ले सकें।

WHO द्वारा एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी बवेरियन नॉर्डिक द्वारा विकसित एमवीए-बीएन वैक्सीन को पूर्व-योग्यता प्रदान की है। यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है और इसे यूरोप और अमेरिका में पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। एकल खुराक की प्रभावशीलता लगभग 76% है, जबकि दोहरी खुराक की प्रभावशीलता लगभग 82% है।



WHO वैक्सीन प्रीक्वालिफिकेशन (PQ) के बारे में:

- ✓ **उत्पत्ति:** WHO ने 1987 में टीकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रीक्वालिफिकेशन प्रणाली शुरू की, ताकि संयुक्त राष्ट्र की स्वरीद एजेंसियां उच्च गुणवत्ता वाले टीके वितरित कर सकें।
- ✓ **प्रीक्वालिफिकेशन की प्रक्रिया:** टीकों को WHO की पूर्व-योग्य सूची में शामिल करने के लिए, टीके के प्रासंगिक आंकड़ों का मूल्यांकन, नमूनों की परीक्षण और विनिर्माण स्थलों का निरीक्षण किया जाता है। सूची में शामिल होना यह नहीं दर्शाता कि WHO द्वारा टीके और विनिर्माण स्थलों को पूरी तरह से मंजूरी दी गई है, क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों (एनआरए) के पास है।
- ✓ **महत्व:** WHO का वैक्सीन प्रीक्वालिफिकेशन कार्यक्रम जोखिमग्रस्त आबादी के लिए टीकों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकारों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे GAVI और यूनिसेफ द्वारा टीकों की स्वरीद में तेजी लाने में मदद करता है और एनआरए को शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने में सहायक होता है।

एमपॉक्स के बारे में:

- ✦ **परिभाषा:** पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाने वाला एमपॉक्स एक जूनोटिक रोग है, जो जानवरों और लोगों के बीच फैलता है।
- ✦ **रोगजनक:** एमपॉक्स वायरस (एमपीएक्सवी), जो ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस का एक लिफ़ाफ़ायुक्त डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है।
- ✦ **खोज:** इसकी खोज 1958 में डेनमार्क में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों में की गई थी, और इसका पहला मानव मामला 1970 में कांगो (डीआरसी) में पाया गया था।
- ✦ **संचारण:** यह वायरस प्रभावित व्यक्ति या पशु के साथ निकट संपर्क, माँ से भ्रूण में (गर्भावस्था के दौरान) आदि के माध्यम से फैलता है।
- ✦ **लक्षण:** त्वचा पर लाल चकत्ते या श्लेष्मिक घाव के साथ बुखार, सिरदर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे लक्षण होते हैं।
- ✦ **WHO की प्रतिक्रिया:** एमपॉक्स को 2022 और 2024 में अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में काम करती है। WHO का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों को संभालना और सभी देशों के लिए स्वास्थ्य मानकों को सुधारना है।

- ✓ **स्थापना:** डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
- ✓ **मुख्यालय:** इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
- ✓ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों की संख्या 194 है, भारत 12 जनवरी, 1948 को WHO का सदस्य बना था।

WHO के प्रमुख कार्य:

- स्वास्थ्य मानक स्थापित करना:** WHO विभिन्न स्वास्थ्य मानकों और दिशानिर्देशों को स्थापित करता है जो देशों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में मदद करते हैं।
- आंकड़े और शोध:** WHO वैश्विक स्वास्थ्य आँकड़ों को एकत्र करता है और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों पर शोध करता है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य संकटों की पहचान और प्रबंधन में मदद मिलती है।
- संकट प्रबंधन:** WHO वैश्विक स्वास्थ्य संकटों जैसे महामारी, प्रकोप और अन्य आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता:** WHO स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है ताकि लोग स्वस्थ जीवन जी सकें और बीमारियों से बच सकें।



राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024

14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस के अवसर पर भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत सचिव श्री वी. श्रीनिवास जी को माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2023-2024 के लिए 300 से कम कर्मियों वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में राजभाषा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को दिया गया।

राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन:

- ✓ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है। विभाग ने राजभाषा हिंदी के उपयोग में लगातार वृद्धि की है और इसके अंतर्गत विभिन्न दस्तावेजों जैसे सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं और प्रेस विज्ञप्तियाँ हिंदी में अनुवाद करने का कार्य भी किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, विभाग ने राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

हिंदी सलाहकार समिति:

- ✓ मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डीएआरपीजी, डीओपीटी और डीओपीएंडपीडब्ल्यू की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति स्थापित की गई है। इस समिति की बैठकें माननीय कार्मिक राज्य मंत्री की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति:

- ✓ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव जी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभाग के प्रमुख और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के अधिकारी सदस्य हैं। यह समिति तिमाही बैठकें आयोजित करती है और संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन:

- ✓ सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग का आकलन करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है और राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इसके साथ ही, हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है।

हिंदी परववाड़ा:

- ✓ 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर विभाग में 14 से 28 सितंबर 2023 तक हिंदी परववाड़ा मनाया गया। इस दौरान 05 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें 88 कार्मिकों ने भाग लिया। विजेताओं को 30 अक्टूबर 2023 को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया गया।
- ✓ हिंदी कार्यशालाएँ: कार्मिकों की हिंदी में सरकारी कामकाज करने की झिझक दूर करने के लिए साल में चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।



मुख्य पहल और निर्देश

राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत हिंदी में दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के प्रशासन और लोक शिकायत खंड को हिंदी में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी में किए गए कार्यों के आधार पर प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है।

अन्य प्रयास:

- ✓ अनुवाद और ध्वनि टाइपिंग पर हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- ✓ विभाग में उप सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों में से 9 अधिकारी 100% हिंदी में कार्य करते हैं।
- ✓ 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर एक सेमिनार आयोजित किया गया।
- ✓ विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, और ई-मेल द्विभाषी रूप में होते हैं।
- ✓ सभी समाचार पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मंगाए जाते हैं।

इन प्रयासों के माध्यम से विभाग हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रचार में निरंतर अग्रसर है।

नाविका सागर परिक्रमा II

भारतीय नौसेना ने समुद्री विरासत को संरक्षित करने और नाविक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नौकायन परंपरा को पुनर्जीवित करने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आईएनएस तरंगिणी, आईएनएस सुदर्शिनी जैसे प्रशिक्षण जहाजों के साथ-साथ आईएनएसवी म्हादेई और तारिणी के जरिए किए गए महासागर नौकायन अभियानों ने भारतीय नौसेना को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।

महिला अधिकारियों का अद्वितीय अभियान: नाविका सागर परिक्रमा II

भारतीय नौसेना की दो साहसी महिला अधिकारी - लेफ्टिनेंट कमांडर रुपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के जल्द ही आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर विश्व परिक्रमा करने के अद्वितीय अभियान 'नाविका सागर परिक्रमा II' के लिए रवाना होंगी। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए दोनों अधिकारी पिछले तीन वर्षों से प्रशिक्षण ले रही हैं।

ट्रांस-ओशनिक अभियान और महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

इन महिला अधिकारियों ने पिछले साल गोवा से केप टाउन होते हुए रियो डी जेनेरियो तक ट्रांस-ओशनिक अभियान में भाग लिया था। इसके बाद, उन्होंने डबल हैंड्रेड मोड में गोवा से श्री विजया पुरम (पहले पोर्ट ब्लेयर) तक नौकायन किया। इस साल, दोनों ने गोवा से मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुइस तक सफल यात्रा पूरी की, जिससे उनके अनुभव और कौशल को और मजबूती मिली है।

सागर परिक्रमा: साहस, कौशल और समानता का प्रतीक:

सागर परिक्रमा एक कठिन यात्रा होगी, जिसमें अत्यधिक कौशल, शारीरिक तंदुरुस्ती और मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होगी। इस अभियान के लिए उन्हें प्रसिद्ध नौकायन विशेषज्ञ कमांडर अभिलाष टॉमी (सेवानिवृत्त) के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह यात्रा भारत के नौकायन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और यह खुले सागर में महिला-पुरुष समानता को भी दर्शाएगी।

ऐतिहासिक अभियान का प्रतीक: 'लोगो' का अनावरण:

इस ऐतिहासिक अभियान के प्रतीक के रूप में भारतीय नौसेना ने 'लोगो' का अनावरण किया है। अष्टकोणीय आकार भारतीय नौसेना का प्रतीक है, जबकि सूर्य और कम्पास नाविकों को चुनौतीपूर्ण समुद्र में मार्गदर्शन करने का प्रतीक हैं। पाल वाली नाव इस साहसिक यात्रा में भाग लेने वालों की जीवदता और हिम्मत का प्रतीक है। यह अभियान महिला-पुरुष समानता को दर्शाता है, बल्कि वैश्विक समुद्री गतिविधियों में भारत की प्रमुखता को भी प्रदर्शित करता है।

ऑपरेशन सद्भाव

भारत सरकार ने तूफान यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव की शुरुआत की है, जिसके तहत वियतनाम को सहायता प्रदान की गई।



ऑपरेशन सद्भाव के अन्तर्गत सहायता:

- **भारतीय नौसेना का सतपुड़ा जहाज म्यांमार रवाना :** भारत ने आईएनएस सतपुड़ा जहाज को 10 टन राहत सामग्री के साथ म्यांमार के बाढ़ प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए रवाना किया है। इसमें सूखा राशन, कपड़े और दवाइयाँ शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने तत्काल राहत पहुंचाने के लिए यह त्वरित कदम उठाया है।
- **वियतनाम को राहत सामग्री भेजी :** भारत ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित उत्तरी वियतनाम के लिए 35 टन मानवीय सहायता सामग्री भेजी है, जिसमें जल शोधन सामग्री, पानी के कंटेनर, कंबल, रसोई के बर्तन, और सौर लालटेन शामिल हैं। यह सहायता विशेष विमान द्वारा 15 सितंबर, 2024 को वियतनाम पहुंचाई गई।
- **भारत-वियतनाम संबंधों की गहराई :** वियतनाम को दी गई मानवीय सहायता भारत और वियतनाम के बीच स्थायी घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है, जो दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है।
- **आपदा राहत में भारत की अग्रणी भूमिका :** ऑपरेशन सद्भाव भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत आसियान क्षेत्र में आपदा राहत (HADR) में भारत के दीर्घकालिक योगदान का हिस्सा है।

तूफान यागी:

हाल ही में, दक्षिण चीन सागर में तूफान यागी विकसित हुआ। इसे बेरिल के बाद इस वर्ष दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जा रहा है। यागी की उत्पत्ति पलाऊ के निकट कम दबाव वाले क्षेत्र में हुई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने इसका नाम यागी रखा।

चमरान-1 उपग्रह

हाल ही में ईरान ने काइम-100 रॉकेट के जरिए अपने चमरान-1 अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया। यह प्रक्षेपण ईरान के एयरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसे पश्चिमी देशों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। उपग्रह को 550 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य कक्षीय पेंटेबाज़ी तकनीक का परीक्षण करना है।



क्षेत्रीय तनाव के बीच प्रक्षेपण:

इस उपग्रह प्रक्षेपण के समय मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का माहौल है, विशेष रूप से चल रहे इजरायल-हमास संघर्ष के कारण। इसके अलावा, यह प्रक्षेपण महसा अमिनी की मृत्यु की दूसरी वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जिसने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था।

पश्चिमी देशों की चिंताएं और ईरान की प्रतिक्रिया:

इस प्रक्षेपण ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में चिंताओं को जन्म दिया है, जो इसे ईरान के अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) कार्यक्रम से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, ईरान का कहना है कि उसकी अंतरिक्ष गतिविधियाँ पूरी तरह से नागरिक और रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हैं।

ईरान के नए राष्ट्रपति के तहत पहला प्रक्षेपण:

यह प्रक्षेपण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के कार्यकाल के तहत पहला सफल प्रक्षेपण है। राष्ट्रपति पेजेशकियन की इस कार्यक्रम पर भविष्य की रणनीति अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह प्रक्षेपण उनके प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM):

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ये मिसाइलें आमतौर पर परमाणु हथियारों से लैस होती हैं और किसी भी देश के लिए एक प्रमुख रणनीतिक हथियार माना जाता है।

ICBM की विशेषताएं:

- दूरी: ICBM की अधिकतम दूरी 5,500 किलोमीटर से अधिक होती है, जिससे वे दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकते हैं।
- गति: ये मिसाइलें अत्यधिक गति से यात्रा करती हैं, जिससे दुश्मन के पास उन्हें रोकने का बहुत कम समय होता है।
- परमाणु हथियार: ICBM आमतौर पर परमाणु हथियारों से लैस होते हैं, जो विनाशकारी क्षमता रखते हैं।

गोरिल्ला: स्व-चिकित्सा व्यवहार से औषधि खोज में मदद की संभावना

हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों का मानना है कि गोरिल्ला के स्व-चिकित्सा व्यवहार से भविष्य में नई औषधि खोज में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह खोज उनके स्वाभाविक उपचार तरीकों का अध्ययन कर नई संभावनाओं को उजागर कर सकती है।



गोरिल्ला:

गोरिल्ला महान वानरों में सबसे बड़े हैं। वे अपने आनुवंशिक कोड का 98.3% हिस्सा मनुष्यों के साथ साझा करते हैं, जो उन्हें हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक बनाता है। लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले मनुष्य और गोरिल्ला का एक सामान्य पूर्वज था।

गोरिल्ला की प्रजातियाँ और वितरण:

दुनिया में गोरिल्ला की दो प्रमुख प्रजातियाँ हैं: पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला।

- ✓ पूर्वी गोरिल्ला: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), युगांडा और रवांडा के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं।
- ✓ पश्चिमी गोरिल्ला: नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और गैबॉन समेत कई देशों में पाए जाते हैं। इनमें से पहाड़ी गोरिल्ला पूर्वी गोरिल्ला की एक उप-प्रजाति है।

गोरिल्ला की विशेषताएँ:

गोरिल्ला बड़े और शक्तिशाली जानवर होते हैं जिनकी छाती और कंधे मजबूत होते हैं।

- नर गोरिल्ला मादाओं से दोगुने भारी होते हैं, उनकी ऊंचाई 1.7 मीटर और वजन 135-220 किलोग्राम तक हो सकता है।
- इनके हाथ मानव जैसे होते हैं और भुजाएं पैरों से लंबी होती हैं।
- सिल्वरबैक नर गोरिल्ला यौन परिपक्वता के दौरान पीठ और जांघों पर चांदी-ग्रे रंग की काठी विकसित करते हैं।

गोरिल्ला का जीवनशैली और व्यवहार:

गोरिल्ला आम तौर पर पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिनमें एक तयस्क सिल्वरबैक नर नेतृत्व करता है।

- ये समूह बहुविवाही होते हैं और नर गोरिल्ला मादा सदस्यों के साथ संभोग करता है।
- वे दिन में सक्रिय रहते हैं और आमतौर पर अंगुलियों पर चलने की विशेष चाल का प्रयोग करते हैं।
- उनका आहार मुख्य रूप से शाकाहारी होता है।

निधि कम्पनियां

हाल ही में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए दो दर्जन से अधिक निधि कंपनियों पर कार्रवाई की है। निधि कंपनियाँ सामान्यतः भारत के गैर-बैंकिंग वित्तपोषण क्षेत्र में कार्य करती हैं और अपने सदस्यों को धन उधार देने और बचत की आदत विकसित करने का काम करती हैं।



निधि कंपनी की विशेषताएँ और कानूनी आवश्यकता:

निधि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 के तहत मान्यता प्राप्त होती है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसके गठन के लिए न्यूनतम सात सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिनमें से तीन सदस्य कंपनी के निदेशक होने चाहिए।

निधि कंपनियों की निषिद्ध गतिविधियाँ:

- ✓ चिट फंड, किराया-खरीद वित्त, पट्टा वित्त, बीमा या प्रतिभूति कारोबार में संलग्न नहीं हो सकती हैं।
- ✓ केवल अपने सदस्यों से ही धन स्वीकार करने और उधार देने की अनुमति है; अन्य किसी भी व्यक्ति से राशि स्वीकार करना या देना सख्त वर्जित है।
- ✓ निधि कंपनियाँ किसी भी तरीके, नाम या रूप में वरीयता शेयर, डिबेंचर या अन्य ऋण साधन जारी नहीं कर सकतीं।
- ✓ अपने सदस्यों के नाम पर चालू खाते खोलने की अनुमति नहीं है।

कंपनी अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई:

हाल की कार्रवाई का उद्देश्य निधि कंपनियों के द्वारा कंपनी अधिनियम की शर्तों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है।

वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2024

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2024 जारी किया गया। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) पांच स्तंभों में देश-स्तरीय साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करता है: कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक, क्षमता विकास और सहयोग। यह सूचकांक देशों की साइबर सुरक्षा प्रगति का आकलन करने के लिए एक नए पांच-स्तरीय विश्लेषण प्रणाली (टियर 1 से टियर 5) का उपयोग करता है।



जीसीआई 2024 की मुख्य बातें:

- ✓ **भारत की स्थिति:** भारत सहित 46 देश टियर 1, यानी "रोल मॉडलिंग" श्रेणी में शामिल हैं, जो सभी पांच साइबर सुरक्षा स्तंभों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।
- ✓ **वैश्विक सुधार:** 2021 के बाद से (जब पिछला GCI प्रकाशित हुआ था), सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया है, और अफ्रीका साइबर सुरक्षा पर सबसे अधिक प्रगति कर रहा है।
- ✓ **डिजिटल सेवाओं का विस्तार:** अधिकांश देश या तो "स्थापित" (टियर 3) हैं या "विकसित" (टियर 4), जिन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया है, लेकिन उन्हें साइबर सुरक्षा उपायों को एकीकृत करना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण मुद्दे:

- ✦ **चिंताजनक खतरे:** रैनसमवेयर हमले, प्रमुख उद्योगों को प्रभावित करने वाले साइबर उल्लंघन, और महंगी प्रणाली रूकावटें।
- ✦ **साइबरक्षमता अंतराल:** कौशल, स्टाफिंग, उपकरण और वित्तपोषण में सीमाएं।
- ✦ **साइबर सुरक्षा ढांचे का संचालन:** साइबर सुरक्षा समझौतों को व्यावहारिक रूप में लागू करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

मुख्य अनुशासार्थ:

- ✦ **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति:** एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति विकसित करना और उसे नियमित रूप से अद्यतन करना।
- ✦ **क्षमता निर्माण:** साइबर सुरक्षा पेशेवरों, युवाओं और कमजोर समूहों के लिए क्षमता निर्माण।
- ✦ **सूचना साझाकरण और सहयोग:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें सूचना साझाकरण और प्रशिक्षण अवसर शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU):

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में दूरसंचार सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 17 मई, 1865 को पेरिस में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!





APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Pathshala

Subject

HISTORY ,POLITY

GEOGRAPHY

ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

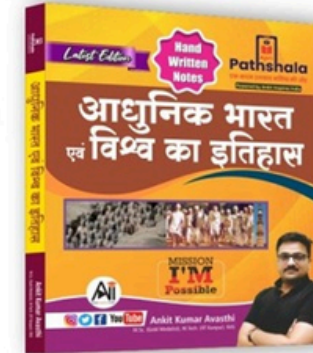
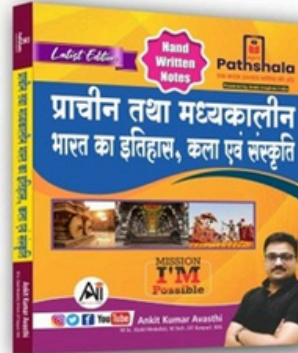
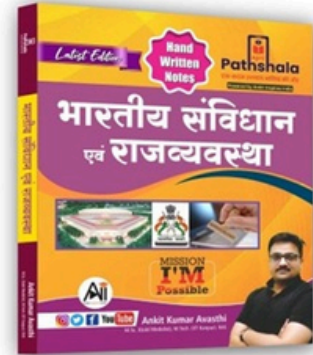
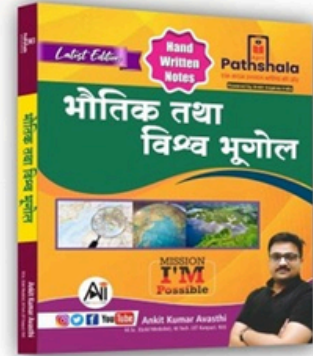
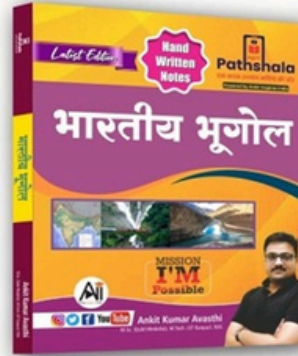
Hand Written
Notes


Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**